10

संख्या- 90 -दो(8)/XXXVI(2)/2012-03-दो(1)/06

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह अधिकरी
संयुक्त सचिव, न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय: जिला न्यायाधीश,उत्तरकाशी के टाईप-V आवासीय भवन निर्माण एवं जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए टाईप-IV के आवासीय भवन निर्माण (टाईप -I के आवास सहित) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-3815/U.H.C./ Admn.B /IX-b/2002, दिनांक: 01 अगस्त, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के टाईप-V आवासीय भवन निर्माण एवं जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए टाईप-IV के आवासीय भवन निर्माण (टाईप-I के आवास सहित) हेतु कमशः ₹ 64,64,000/- एवं ₹ 73,22,000/- के दो पुनरीक्षित आगणन प्रेषित करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

2- उपरोक्त के कम में शासनादेश संख्या-2-दो(1)/XXXVI(1) /06, दिनांक: 25.05.2006 तथा पुनरीक्षित शासनादेश संख्या-10-दो(8)/XXXVI(2)/2009-2-दो(1)/06, दिनांक: 19.05.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के टाईप-V के आवासीय भवन के निर्माण हेतु कमशः ₹ 34,40,000/- की वित्तीय स्वीकृति एवं ₹ 5,62,000/- की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-5-दो(1)/XXXVI(1) /06, दिनांक: 09.06.2006 तथा पुनरीक्षित शासनादेश संख्या-22-दो(8)/XXXVI(1)/2007-5-दो(1)/06, दिनांक: 24.08.2007 का भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए टाईप-IV के आवासीय भवन निर्माण हेतु कमशः ₹ 47,66,000/- की वित्तीय स्वीकृति एवं ₹ 2,46,000/- की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

4- अतः इस सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-3815/U.H.C./ Admn.B /IX-b/2002, दिनांक: 01 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के टाईप-V आवासीय भवन निर्माण एवं जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए टाईप-IV के आवासीय भवन निर्माण (टाईप-I के आवास सहित) हेतु निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन ₹ 64.64 लाख + ₹ 73.22 लाख के सापेक्ष **₹ 63.15 लाख + ₹ 67.05 लाख अर्थात ₹ 130.20 लाख (₹ एक करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र) पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय**

अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्तर-2 व 3 में सन्दर्भित उपरोक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹ 40.02 लाख + ₹ 50.12 लाख अर्थात ₹ 90.14 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 40.06 लाख (₹ चालीस लाख छः हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(5) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(10) उक्त कार्यो को इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जायेगा ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) आगणन गठिन करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(14) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नही करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2013 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(16) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-60/P/XXVII(5)/2012, दिनांक: 27 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित् व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट कम्प्यूटरीकृत आधार पर आबंटित किये जाने हेतु संलग्न **अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-S1211040233, दिनांक: 29 नवम्बर, 2012,** के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकरी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 90 -दो(8)/XXXVI(2)/2012-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकरी)
संयुक्त सचिव ।